वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) जी, हां ।

(ख) जैसे कुछ राज्यों में योजना समाप्त कर दी गई है, मध्य प्रदेश को वर्ष 1997-98 के लिए कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किए गये हैं ।

Corruption in Apparel Export Promotion Council

2468. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it has been reported that exporters of silk garments alleged that corruption in Apparel Export Promotion Council offices was hindering their export efforts;

(b) whether other tactics of corrupt practices by officials of AEPC have also been explained to the Textile Secretary of Government;

(c) whether Government propose to take some action on these allegations of exporters; and

(d) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R. L. JALAPPA): (a) to (d) In a Seminar held of NIFT Campus, New Delhi on July 23, 1997, some silk exporters complained about alleged delays in certification of shipping documents for silk garments by the Apparel Export Promotion Council (AEPC). The AEPC has reported that no case has come to their notice recently where there has been any delay in certification of shipping documents for silk garment exports by them.

कपास उत्पादन

2469. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपास उत्पादन राज्य और उनके द्वारा उत्पादित वर्ष-वार उत्पाद क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या देश में कपास के उत्पादन मे कुछ वर्षों से कमी आ रही है ;

(ग) क्या किसानों को उनके उत्पादन का पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है ;

(घ) 1993-94, 1994-95 1995-96 और 1996-97 के दौरान देश में प्रति हैक्टेयर कपास का उत्पादन कितना हुआ है ;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कपास की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में वर्षा की कमी और अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण कपास के उत्पादन में काफी कमी आयी है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) पिछले तीन कपास मौसम के दौरान कपास के राज्यवार उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) जी नहीं । सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद कीमतें प्राप्त हों। कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊंची चल रही हैं।